भारतीय खाद्य निगम के एकक

5637. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय खाद्य निगम के कितने एकक हैं ;

(ख) खाद्यान्न वसूली के विकेन्द्रीयकरण के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न एककों द्वारा कितने खाद्यान्न की वसूली की गई ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनका वार्षिक व्यय कितना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय देश में भारतीय खाद्य निगम के 1894 यूनिट कार्य कर रहे हैं जिनमें उसका प्रधान कार्यालय, जोनल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पत्तन परिचालन कार्यालय, जिला कार्यालय, डिपो तथा चावल, मक्का और दाल मिलें शामिल हैं ।

(ख) निगम के विभिन्न यूनिटों द्वारा अपनी स्थापना से 21 मार्च, 1977 तक कुल 678.3 लाख मीटरी टन खाद्यान्न वसूल/खरीदे गये थे ।

(ग) निगम में 31 मार्च, 1977 को 63057 कर्मचारी कार्य कर रहे थे और वर्ष के दौरान उन पर 47.5 करोड़ रुपए व्यय हुये थे ।

Accumulation of Nitrogen Fertilizers

5638. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether there is a glut of accumulated stock of Nitrogen Fertilizer with the manufacturers, with the result that its further production is likely to be hit;

(b) whether Government is lifting the restrictions on Inter-State movement of Fertilizers to liquidate the accumulated stock; and

(c) if not, the reason therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT BARNALA): (a) The build up of stock with the manufactures during the period March to the middle of June each year is a seasonal phenomenon. According to available information, the stock of nitrogenous fertilizers with the manufacturers was 2.95 lakh tonnes of nitrogen on the 15th May, 1977 as compared to 3.22 lakh tonnes of nitrogen as on the 15th May, 1976. With the onset of the monsoon and the sowing season, the stocks with the manufacturers have begun moving out.

(b) No, Sir.

(c) The restrictions imposed under the Fertilizer Movement Control Order are only to enable the formulation of a coordinated and rational supply plan for allocation of fertilizers (both indigenous and imported) to different States and Union Territories. This Supply Plan is drawn up in consultation with the Railway Ministry and the manufacturers. This not only ensures smooth and uninhibited supply of fertilizers to State Governments but also avoids long haulages and criss-cross movement. The movement of fertilizer on a priority basis by the Railways is ensured and expenditure on freight is minimised.

असिंचित भूमि

5639. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितनी असिंचित कृषि भूमि है ; और

(ख) उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला): (क) और (ख). वर्ष 1974–75 को समाप्त होने वाले 5 वर्षों के दौरान बोया गया ऐसा निवल क्षेत्र, जिसके लिए सिंचाई सुविधाएं नहीं हैं, 1973–74 में 1103 लाख हैक्टेयर तथा 1974–75 में 1047 लाख हैक्टेयर था । इन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

असिंचित क्षेत्र के राज्य-वार आंकड़े

राज्य	हजार हैक्टार में	
	1973–74	1974–75
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	8,355	8,146
असम	1,886(अ)	1,971(अ)
बिहार	6,054	5,821
गुजरात	8,126(अ)	6,571(अ)
हरियाणा	1,830	1,740
हिमाचल प्रदेश	462	453
जम्मू तथा काश्मीर	387	393
कर्नाटक	9,029	9,039
केरल	1,745	1,743
मध्य प्रदेश	16,915	16,881
महाराष्ट्र	16,852	16,695
मणिपुर	75	75
मेघालय	116	116
नागालैंड	74	75
उड़ीसा	5,095	4,792
पंजाब	1,137	909
राजस्थान	13,589	11,311
तमिलनाडु	3,359	3,116

(1)	(2)	(3)
त्रिपुरा	213(अ)	210(अ)
उत्तर प्रदेश . . .	9,927	9,387
पश्चिम बंगाल	4,696(अ)	4,931(अ)
संघ राज्य क्षेत्र . . .	337	344
अखिल भारत .	110,259	104.719

अ: अस्थायी

†असिंचित परिस्थितियों के अन्तर्गत दिखाये गए क्षेत्र को बुवाई के कुल क्षेत्र तथा कुल सिंचित क्षेत्र के अन्तर से लिया गया है। इन आंकड़ों को भूमि उपयोग आंकड़ों के एक भाग के रूप में इकट्ठा किया गया था ।

गुजरात के लिए सिंचाई योजनाएं

5640. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग के पास गुजरात राज्य की कितनी और कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं मंजूर करने के लिए पड़ी हैं ;

(ख) गुजरात सरकार ने ये योजनाएं केन्द्र सरकार के पास कब भेजी थीं;

(ग) योजनाएं मंजूर करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन योजनाओं की मंजूरी कब तक दी जायेगी ; और

(घ) 31 मार्च, 1977 तक गुजरात राज्य की कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं मंजूर करने के लिए पड़ी थीं और उनके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग). इस समय गुजरात की पांच बृहद और छः मध्यम सिंचाई स्कीमों की केन्द्रीय जल आयोग में विभिन्न जल आयोग में विभिन्न चरणों में जांच की जा रही है । इन स्कीमों के नाम, इनके प्राप्त होने की तारीख और उनकी जांच की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) 31 मार्च, 1977 को गुजरात की छः बृहद और सात माध्यम स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग में बिचाराधीन थीं । एक बृहद् स्कीम नामशः कर्जन और एक मध्यम स्कीम नामशः कालुभार इस बीच अनुमोदित कर दी गई है।। शेष 11 सकीमों (5 बृहद और 6 मध्यम) की स्थिति, जिनका हवाला ऊपर भाग (क) से (ग) में भी दिया गया है, संलग्न विवरण में दी गई है ।